



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2, 2018/चैत्र 12, 1940

No. 208]

NEW DELHI, MONDAY APRIL 2, 2018/CHAITRA 12, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2018

सं. 29/2018-सीमा शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 329(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 28 की उपधारा (1) के उपवाक्य (क) के परंतुक के साथ पठित धारा 157 की उपधारा (2) के उपवाक्य (ड) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.- (1) इस विनियमावली को प्री- नोटिस कॉन्सल्टेशन रेगुलेशन, 2018 कहा जाएगा।
(2) ये सरकारी राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

- परिभाषा.- इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से अभिप्राय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है;

(ख) “परामर्श” से अभिप्राय उस आधार के सम्प्रेषण से है जो कि यथोचित अधिकारी के जानकारी में है और जो उस व्यक्ति को नोटिस जारी किए जाने के बारे में है जिस पर शुल्क या ब्याज लगाया जाना

है जिससे कि उक्त व्यक्ति का प्रत्युत्तर प्राप्त हो सके और उक्त व्यक्ति के अभ्यावेदन पर विचार किया जा सके;

(ग) “नोटिस” से अभिप्राय उक्त अधिनियम की धारा 28 की उप धारा (1) में संदर्भित कारण बताओ नोटिस से है।

3. नोटिस जारी किए जाने के पूर्व परामर्श का तरीका.- नोटिस जारी किए जाने के पूर्व निम्न रूप से परामर्श किया जाएगा:-

(1) नोटिस जारी किए जाने के पूर्व, यथोचित अधिकारी उस व्यक्ति को जिससे कि शुल्क या ब्याज की वसूली की जानी है, अपने नोटिस जारी किए जाने की इच्छा से लिखित में अवगत कराएगा जिसमें यथोचित अधिकारी की जानकारी में रहने वाले उन आधारों को भी स्पष्ट किए जाना होगा जिनके आधार पर ऐसी नोटिस जारी किए जाने का प्रस्ताव है और नोटिस जारी किए जाने के पूर्व परामर्श की यह प्रक्रिया उक्त अधिनियम की धारा 28 की उप धारा (3) में उल्लिखित समय सीमा की समाप्ति के यथा संभव कम से कम 2 महीने पहले से शुरू की जानी होगी।

(2) वह व्यक्ति जिससे कि शुल्क या ब्याज को वसूला जाना है उप विनियम (1) में संदर्भित सम्प्रेषण की तारीख से 15 दिन के भीतर इस प्रकार संप्रेषित किए गए आधारों के बारे में अपनी बात को लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा:

बशर्ते कि यदि जिस व्यक्ति को ऐसे आधार पर नोटिस जारी किए जाने का प्रस्ताव है उससे विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यथोचित अधिकारी आगे कोई सम्प्रेषण किए बिना उक्त व्यक्ति को ऐसे नोटिस जारी किए जाने की कार्यवाही कर सकेगा:

बशर्ते और भी कि अपनी बात कहते समय वह व्यक्ति जिससे कि शुल्क या ब्याज की वसूली की जानी है, यह स्पष्ट करेगा कि क्या वह यथोचित अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई किए जाने की इच्छा रखता है या नहीं।

(3) यथोचित अधिकारी यदि अनुरोध किया जाए तो उप-विनियम (2) में संदर्भित याचना की प्राप्ति के 10 दिन के भीतर उस व्यक्ति की सुनवाई कर सकता है और धारा 28 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए यह निर्णय ले सकता है कि क्या किसी नोटिस को जारी किए जाने की जरूरत है या नहीं:

बशर्ते कि इस विनियम में अनुमति प्राप्त सुनवाई के बारे में किसी भी कारण से कोई भी आस्थगन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(4) जहां यथोचित अधिकारी ऐसे परामर्श के पश्चात इस निर्णय पर पहुंचता है कि उप-विनियम (1) के अंतर्गत संप्रेषित आधार के संदर्भ में नोटिस किए जाने की जरूरत नहीं है तो वह, संबन्धित व्यक्ति को एक साधारण से पत्र के माध्यम से इसकी सूचना दे देगा।

(5) इस विनियम में प्रदत्त परामर्श की प्रक्रिया विनियम (1) में यथा प्रदत्त आधारों के सम्प्रेषण की तारीख से साठ दिन के भीतर पूरी की जानी होगी।

(6) जहां किसी व्यक्ति के बारे में प्रस्तावित नोटिस तो उसी मुद्दे पर है लेकिन यह अलग अवधि के लिए है या नोटिस पूर्व परामर्श के बाद कागजात जारी किए गए हों वहाँ यथोचित अधिकारी बिना आगे और परामर्श के अगली अवधियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्यवाही कर सकता है।

[फा. सं. 450/49/2018-सीमा शुल्क IV]

जुबैर रियाज़, निदेशक (सीमाशुल्क)

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**New Delhi, the 2nd April, 2018**No. 29/2018-Customs (N.T.)**

G.S.R. 329(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 157 read with the proviso to clause (a) of sub-section (1) of section 28 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Pre-notice Consultation Regulations, 2018.
- (2) They shall come into effect on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.- In these regulations, unless the context otherwise requires,-
 - (a) “Act” means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);
 - (b) “consultation” means communication of the grounds known to the proper officer for issuance of notice to the person chargeable with duty or interest in order to elicit the response of the person and consideration of the representation of the said person;
 - (c) “notice” means a show cause notice referred to in sub-section (1) of section 28 of the Act.
3. Manner of conducting pre-notice consultation.- Pre-notice consultation shall be made in the following manner:-
 - (1) Before the notice is issued, the proper officer shall inform, in writing, the person chargeable with duty or interest of the intention to issue the notice specifying the grounds known to the proper officer on which such notice is proposed to be issued and the process of pre-notice consultation shall be initiated as far as possible atleast two months before the expiry of the time limit mentioned in sub-section (3) of section 28 of the Act.
 - (2) The person chargeable with duty or interest may, within fifteen days from the date of communication referred to in sub regulation (1), make his submissions in writing on the grounds so communicated:

 Provided that if no response is received, from the person to whom the grounds on which notice is proposed to be issued, is received within the specified time, the proper officer shall proceed to issue the notice to the said person without any further communication:

 Provided further that while making the submissions, the person chargeable with duty or interest shall clearly indicate whether he desires to be heard in person by the proper officer.
 - (3) The proper officer, may if requested, hear the person within ten days of receipt of the submissions referred to in sub-regulation (2) and subject to the provisions of section 28, decide whether any notice is required to be issued or not:

 Provided that no adjournment for any reason shall be granted in respect of the hearing allowed under this regulation.
 - (4) Where the proper officer, after consultation, decides not to proceed with the notice with reference to the grounds communicated under sub-regulation (1), he shall, by a simple letter, intimate the same to the person concerned.
 - (5) The consultation process provided in these regulations shall be concluded within sixty days from the date of communication of grounds as provided in sub-regulation (1).

-
- (6) Where the proposed show cause notice is in respect of a person to whom a notice on the same issue but for a different period or documents has been issued after pre-notice consultation, the proper officer may proceed to issue the show cause notice for subsequent periods without any further consultation.

[F. No. 450/49/2018 – Cus-IV]

ZUBAIR RIAZ, Director (Customs)